कम्युनिटी मैटर्स

Outlook

www.outlookindia.com

जून, 2023

विशेषांक

UNFPA

बदलाव से बेहतर होता जीवन

काम ज्यादा, बातें कम

जब विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2023 जारी की गई, जिसने बताया कि भारत जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया में पहले स्थान पर पहुंच गया है, तब यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड चर्चाओं में आया। संयुक्त राष्ट्र की सेक्सुअल एवं प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी भारत में बहुत नजर नहीं आती है। ऐसा इसलिए है कि भारत जैसे विविधता पूर्ण देश में ऐसे कई संवेदनशील मुद्दे हैं, जिनके लिए यह एजेंसी काम करती है।

यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का लो-प्रोफाइल रह कर काम करना फायदेमंद साबित हो रहा है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड एजेंसी, सरकार एवं अन्य सहयोगियों के साथ दिन रात मेहनत कर रही है और बदलाव की अलख जगाने में जुटी है। यह एजेंसी बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान में विकास के संकेतकों को ऊपर उठाने का काम कर रही है, जिसे राष्ट्र का सर्वांगीण विकास हो रहा है।

आउटलुक में हम विश्वास करते हैं कि ऐसी प्रभावशाली कहानियों को जनसामान्य तक पहुंचाया जाना चाहिए। न केवल इसलिए कि इनसे समाज को सकारात्मकता मिलेगी बल्कि इसलिए भी कि अनुभवों के आदान प्रदान से ही भविष्य में जनकल्याणकारी योजनाओं के निर्माण में मदद मिलेगी। हमें प्रसन्नता है कि यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के साथ साझेदार बनकर हम इस सकारात्मक संदेश को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं।

राजीव तिकू
संस्करण संपादक

6
राजस्थान
महिलानुकूल पंचायत
महिलाओं एवं बालिकाओं के विकास संकेतकों को बेहतर करने के लिए महिलाओं के अनुकूल ग्राम पंचायत का वातावरण बनाया जा रहा है।

9
मध्य प्रदेश
जीवन कौशल का विकास
जीवन कौशल संबंधी शिक्षा किशोरों और युवाओं को अपने स्वास्थ्य और सलामती के लिए समुचित निर्णय लेने में सक्षम बनाती है।

13
ओडिशा
डाटा लाभांश
बुनियादी ढांचे में सुधार करने एवं संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए सिनापाली नुआपाड़ा में डाटा आधारित मुहिम चलाई जा रही है।

16
बिहार
युवा जीवन में बदलाव
मदरसों में पढ़ने वाले लाखों मुस्लिम विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर करने हेतु किशोरों के जीवन कौशल से संबंधित तालीम -ए-नौबलीगान पहल बिहार में शुरू की गई है।

Outlook
(Special Issue)
....
EDITOR, *OUTLOOK BUSINESS* Suchetana Ray
EDITION EDITOR Rajiv Tikoo
EXECUTIVE EDITOR Nishant
DESK Chitra Nair, Shailaja Tripathi and Naina Gautam
SENIOR DESIGNER Vinay Dominic

BUSINESS OFFICE
CHIEF EXECUTIVE OFFICER Indranil Roy
Sandip Kumar Ghosh
Meenakshie Mehta
Shrutika Dewan
Sukanya Chatterjee
Shashank Dixit
Gagan Kohli

HEAD OFFICE
AB-10, S.J. Enclave, New Delhi - 110 029
Tel: 011-71280400; Fax: 26191420
Customer care helpline: 011-71280433, 71280462, 71280307
e-mail: outlook@outlookindia.com
For editorial queries: edit@outlookindia.com
For subscription helpline: yourhelpline@outlookindia.com

Printed and published by Indranil Roy on behalf of Outlook Publishing (India) Pvt. Ltd. Printed at MP Printers (A Unit of DB Corp Ltd) B-220, Phase-II, Noida 201305, Gautam Budh Nagar (UP) and published from AB-10, S.J. Enclave, New Delhi-110 029
Total number of pages 20 including covers

Cover photographs (front, front inside and back): UNFPA
....

UNFPA INDIA TEAM MEMBERS
CHIEF, POLICY AND PARTNERSHIPS Jaydeep Biswas
COMMUNICATIONS AND MEDIA SPECIALIST Pinky Pradhan
COMMUNICATIONS AND MEDIA ANALYST Avani Singh
HEAD OF OFFICE - RAJASTHAN Deepesh Gupta
HEAD OF OFFICE - BIHAR Keerti
HEAD OF OFFICE - ODISHA Mohammad Nadeem Noor
HEAD OF OFFICE - MADHYA PRADESH Sunil Jacob

POINT AND SHARE
Now, open Outlook magazine on your smartphone instantly.
Point your phone's scanner on the code and align it in the frame.
You will be guided instantly to our website, www.outlookindia.com
This is useful to share our stories on social media or email them.

एंड्रिया वोजनार
यूएनएफपीए इंडिया की प्रतिनिधि
देश निदेशक भूटान

प्रस्तावना

यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड संयुक्त राष्ट्र की सेक्सुअल एवं प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी है। इसका उद्देश्य एक ऐसी दुनिया का निर्माण करना है, जहां गर्भधारण से लेकर प्रसव की सारी प्रक्रिया बहुत सरल एवं सुरक्षित ढंग से सम्पन्न हो।

भारत में हमारा ध्यान सेक्सुअल एवं प्रजनन स्वास्थ्य को बेहतर करने की ओर है। इसके साथ ही हम व्यक्तित्व निर्माण, लैंगिक समानता, मानव अधिकार और जनसंख्या मामलों को लेकर कार्य करते हैं।

हम अपने सहयोगियों एवं सरकारी संस्थाओं के साथ तालमेल बैठाकर बिहार,मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा जैसे राज्यों में नवीन प्रयोग कर रहे हैं।

उदाहरण के लिए बिहार में तालीम -ए -नौबलीगान पहल के तहत सरकारी मदरसों में पढ़ने वाले गरीब मुस्लिम विद्यार्थियों को बेहतर ढंग से शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। इस प्रयास को पूरे अनुसंधान के साथ किया जा रहा है, जिससे कि सिस्टम की सभी कमियों को दूर किया जा सके।

मध्य प्रदेश में लाइफ स्किल्स एजुकेशन पहल के माध्यम से किशोर एवं किशोरियों को उनके स्वास्थ्य एवं बेहतर भविष्य हेतु जागरूक किया जा रहा है, जिससे वह एकजुट होकर बाल विवाह और लैंगिक असमानता जैसी कुरीतियों से लड़ें।

राजस्थान में, ग्राम पंचायतों में बालिकाओं के अनुकूल वातावरण विकसित किया गया है। इन ग्राम पंचायतों की मदद से, राज्य के महिला एवं बालिका संकेतकों को बेहतर किया जा रहा है। किशोरियों के समूह युवा लड़कियों को सामाजिक, आर्थिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियां उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे वह बाल विवाह, लैंगिक असमानता के खिलाफ आवाज उठा सकें।

ओडिशा में स्थित यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के राजकीय ऑफिस द्वारा डाटा विश्लेषण का इस्तेमाल कर के स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए कार्य किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि मातृ मृत्यु दर में कमी आई और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा मिले।

आउटलुक के इस विशेषांक के माध्यम से यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड द्वारा किए जा रहे सकारात्मक कार्यों को जनसामान्य तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे न केवल जागरूकता बढ़ेगी बल्कि उम्मीद की कहानियों से सीख लेकर उज्ज्वल भविष्य की नींव रखी जा सकेगी।

आने वाले समय में हम बदलाव की और भी कहानियों को आपसे साझा करने का प्रयास करेंगे और विशेष रूप से युवाओं एवं महिलाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए समर्पित रहेंगे।

स्रोत: यूएनएफपीए

लैंगिक मुद्दों को मुख्यधारा में शामिल करना उद्देश्य

भारत में यूएनएफपीए मुख्य रूप से चार क्षेत्रों में काम करती है। यह चार क्षेत्र हैं - सेक्सुअल एवं प्रजनन स्वास्थ्य में सुधार, युवाओं के भविष्य, लैंगिक समानता एवं मानवाधिकार और जनसंख्या मामले।

यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड (यूएनएफपीए) की स्थापना यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल सेक्सुअल एवं रिप्रोडक्टिव एजेंसी के रूप में साल 1969 में हुई थी। 150 से अधिक देशों में सक्रिय यह एजेंसी, सेक्सुअल एवं प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं को प्रमोट करती है। इसमें परिवार नियोजन, मातृ स्वास्थ्य सेवा, यौन संचारित रोगों से बचाव एवं इलाज शामिल है। यूएनएफपीए लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण की भी पैरवी करता है।भारत में यूएनएफपीए मुख्य रूप से चार क्षेत्रों में काम करती है। यह चार क्षेत्र हैं - सेक्सुअल एवं प्रजनन स्वास्थ्य में सुधार, युवाओं के भविष्य, लैंगिक समानता एवं मानवाधिकार और जनसंख्या मामले।

सेक्सुअल एवं प्रजनन स्वास्थ्य

भारत में प्रजनन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, यूएनएफपीए भारत सरकार और राज्य सरकारों की स्वास्थ्य योजनाओं को सहयोग करने का कार्य करती है। यूएनएफपीए उन सभी योजनाओं को सहयोग करती है, जिनका लक्ष्य परिवार नियोजन विकल्पों को उपलब्ध कराना और शिशु एवं मातृ मृत्यु दर को कम करना है। यूएनएफपीए प्रोगाम मैनेजमेंट का काम करती है। इसके तहत मानव संसाधन की संख्या बढ़ाई जाती है और उनके कौशल विकास के लिए कार्य किया जाता है।

युवा सशक्तिकरण

यूएनएफपीए युवाओं और किशोरावस्था में प्रवेश करने वाले नागरिकों के अधिकारों में निवेश करती है। यूएनएफपीए डाटा एकत्रित करने से लेकर शोषित लोगों की पहचान करने का कार्य करती है। इसी कड़ी में शिक्षा व्यवस्था में सुधार,सेक्सुअल एवं प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतरी और आजीविका सृजन की योग्यता विकसित करने हेतु प्रयास किए जाते हैं। एजेंसी स्कूलों में लाइफ स्किल्स एजुकेशन को बढ़ावा देती है। यूएनएफपीए किशोरावस्था में प्रवेश करने वाले लोगों को सेक्सुअल एवं प्रजनन स्वास्थ्य के विषय में सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराती है, जिससे कि उन्हें विभिन्न परिस्थितियों में परेशानी का सामना न करना पड़े। एजेंसी किशोरियों को जागरूक करने के साथ ही युवाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास करती है।

मानवाधिकार और लैंगिक समानता

यूएनएफपीए ऐसी योजनाओं को संचालित करती है, जिनके माध्यम से युवा स्त्रियों और बालिकाओं को स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवा उपलब्ध होती है। इसके अतिरिक्त कार्यक्षेत्र में किस तरह बेहतर प्रदर्शन किया जाए, इसका ज्ञान भी यूएनएफपीए द्वारा स्त्रियों को दिया जाता है। यूएनएफपीए परिवारों, सामुदायिक संगठनों, स्थानीय नेताओं के साथ मिलकर ऐसे प्रयास करती है, जिससे कि समाज में फैली लैंगिक असमानता समाप्त हो। यूएनएफपीए महिलाओं से होने वाली हिंसा के मामलों को कम करने और हिंसा होने पर पीड़ित महिला के लिए उचित स्वास्थ्य सुविधा सुनिश्चित करने के लिए कार्य करती है।

जनसंख्या मामले

जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बड़ा परिवर्तन आया है। ऐसे में यूएनएफपीए का रोल अहम हो जाता है। यूएनएफपीए सरकार के साथ मिलकर ऐसे युवाओं से जुड़े मुद्दों पर काम करती है, जो अभी काम भी कर रहे हैं और उम्रदराज भी हो रहे हैं। यूएनएफपीए मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने, लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए भी कार्य करती है।

स्रोत: यूएनएफपीए

राजस्थान

महिलानुकूल पंचायत

यूएनएफपीए ने सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही योजनाओं का समर्थन किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं का समर्थन कर के और महिलाओं के अनुकूल ग्राम पंचायत बनाकर यूएनएफपीए ने राज्य में विकास संकेतकों को बेहतर किया है।

शैलजा त्रिपाठी

19 साल की प्रियंका मीणा, राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के डेकवा गांव में एक छोटे से कच्चे मकान में रहती हैं। उनका किसान परिवार किसी अन्य के खेतों में मजदूरी कर के सालाना 50 हजार रूपये की कमाई करता है। अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रियंका को साल 2016 में कक्षा 8 के बाद स्कूल छोड़ना पड़ा। आज प्रियंका जयपुर में रहकर 9000 रूपये प्रति माह कमा रही है।

प्रियंका की जिन्दगी में बदलाव लाने का कार्य साथिन (ग्राम पंचायत - महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान) ने किया, जहां से उसकी सामाजिक, आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित हुई। साथिन जैसे महिलाओं के समूह यूएनएफपीए और राजस्थान सरकार के महिला सशक्तिकरण विभाग द्वारा मिलकर स्थापित किए गए हैं।

समूह में होने वाले विमर्श और चर्चाओं से प्रियंका ने जाना कि शिक्षा से आर्थिक स्वतंत्रता हासिल की जा सकती है। तब प्रियंका ने अपने परिवार से बात की और दोबारा स्कूल जाना शुरू किया। प्रियंका ने अपनी मेहनत के बल पर दसवीं की परीक्षाओं में 67 प्रतिशत अंक प्राप्त किए। प्रियंका के शानदार प्रदर्शन से प्रभावित होकर उसके परिवार ने उसे ब्लॉक स्तर पर राज्य सरकार द्वारा संचालित कौशल विकास कार्यक्रम में भेजने का निर्णय लिया। छह महीने का कोर्स करने के बाद प्रियंका को जयपुर में रोजगार मिल गया। अपनी इस उपलब्धि के बारे में प्रियंका कहती हैं "साथिन समूह से जुड़ने के बाद मुझे प्रेरणा मिली और अवसर प्राप्त हुए।इससे मेरे आत्म विश्वास मुं वृद्धि हुई, जिसके बल पर मैं जयपुर जैसे शहर में काम कर रही हूं।" प्रियंका के पिता कैलचंद मीना कहते हैं "सरकार और यूएनएफपीए के सहयोग से संचालित कार्यक्रम के कारण आज मेरी बेटी जयपुर में काम कर रही है। यह हमारे लिए अविश्वसनीय है। यह सहयोग सभी लड़कियों को निरंतर रूप से मिलना चाहिए।"

> मुझे बालिका समूह से प्रेरणा मिली और तभी मुझे अवसर प्राप्त हुए। इसने मेरे आत्म विश्वास को बढ़ाने का काम किया, जिस कारण आज मैं जयपुर जैसे शहर में काम कर रही हूं।
>
> **प्रियंका मीणा**
> सवाई माधोपुर

प्रियंका की तरह ही कई और लड़कियां हैं, जो संघर्ष के सामने चट्टान बनकर खड़ी हैं।18 साल की मंजू की शादी, अपनी बड़ी बहन के विवाह के दौरान ही 2021 में हो गई थी, जिससे कि परिवार पर शादी के कारण पड़ने वाले भार में कमी आए। बालिका समूह से मंजू को बाल विवाह के दुष्परिणामों की जानकारी मिली। बालिका समूह से मंजू को हिम्मत मिली और उसने अपने माता पिता से बात की। इसका नतीजा यह हुआ कि मंजू ने अपने पति के घर जाना स्थगित कर दिया और पुनः पढ़ाई शुरू की।

मंजू आत्म निर्भर बनना चाहती है और

स्रोत: यूएनएफपीए

वह शिक्षिका बनने के लक्ष्य के प्रति समर्पित है। वह बीए की पढ़ाई के साथ, छह महीने का कंप्यूटर प्रशिक्षण कोर्स भी कर रही है। इसके साथ ही मंजू सरकारी स्कूल में शिक्षिका बनने के लिए परीक्षा की तैयारी भी कर रही है। मंजू को यकीन है कि वह जल्द ही दूसरों को शिक्षित करना और ज्ञान देना प्रारंभ कर देगी। मंजू कहती हैं "मुझे गर्व है कि मैं ऐसे समय में कंप्यूटर का ज्ञान प्राप्त कर रही हूं, जब हमारे समाज में लड़कियां शिक्षा और प्रशिक्षण गतिविधियों से वंचित हैं।"मंजू के पिता कहते हैं "मैं अपनी बेटी के सपनों को पूरा करने के लिए सभी प्रयास करूंगा। मैं उसे तब तक उसके पति के पास नहीं भेजूंगा, जब तक उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती।"

प्रियंका और मंजू सिर्फ सवाई माधोपुर जिले के लिए नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के लिए प्रेरणा का केंद्र हैं। बीते कुछ वर्षों में राजस्थान में बाल विवाह की घटनाओं में 10 प्वाइंट की कमी आई है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के अनुसार 35.4 प्रतिशत महिलाओं की शादी 18 साल से पहले हुई थी। जबकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार यह आंकड़ा 25.4 प्रतिशत तक आ गया है। यह राज्य सरकार, केंद्र सरकार और यूएनएफपीए के साझा प्रयासों से ही संभव हुआ है।

यूएनएफपीए ने सरकार की महिला सशक्तिकरण योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को भी समर्थन दिया है। यह योजना भारत सरकार ने साल 2015 में बालिकाओं के विकास हेतु शुरू की थी।

यूएनएफपीए ने महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ मिलकर गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत का कार्यक्रम शुरू किया है। इसकी शुरुआत अगस्त 2018 में सवाई माधोपुर जिले में 7 ग्राम पंचायत से हुई थी। आज राज्य के 33 जिलों में बालिकाओं के अनुकूल ग्राम पंचायत तैयार की गई हैं। हर जिले में 2 ग्राम पंचायत इसी कार्यक्रम के तहत बनाई गई हैं।

गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को उनके अधिकारों

स्रोत: यूएनएफपीए

मुख्य बिंदु

महिलाओं की संख्या (20-24 वर्ष) 18 से कम उम्र की विवाहितों की संख्या घटी

35.4% (एनएफएचएस-4) से

25.4% (एनएफएचएस-5)

लड़कियों की साक्षरता दर बढ़ी

56.5% (एनएफएचएस -4) से

64.7% (एनएफएचएस-5)

के प्रति जागरूक करना है। ऐसा माहौल तैयार करना है, जहां बालिकाएं अपने निर्णय स्वयं ले सकें। वह अपनी प्रतिभा को पहचान सकें और अपने सपनों का आसमान छू सकें।

गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत बालिकाओं के सामाजिक, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रयासरत है। इसका मूल उद्देश्य है कि लैंगिक असमानता और बाल विवाह जैसी कुरीतियों को दूर किया जाए।

एक्शन ग्रुप को पंचायती राज के कर्मचारियों, स्थानीय युवक, युवतियों और जन प्रतिनिधियों के सहयोग से तैयार किया गया है। एक्शन ग्रुप का उद्देश्य ऐसी ग्राम पंचायत की स्थापना है, जहां महिलाएं निर्भीक महसूस कर सकें और उनका सर्वांगीण विकास संभव हो। इसके लिए कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए गए हैं। महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है।

यह कोशिशों का ही परिणाम है कि बीते तीन वर्षों में ग्राम पंचायत में एक भी बाल विवाह नहीं हुआ है। एएनसी चेक अप के लिए पंजीकरण कराने वाली महिलाओं की संख्या 73 प्रतिशत से बढ़कर 91 प्रतिशत हो गई है। बालिकाओं में टीकाकरण भी 80 प्रतिशत से बढ़कर 90 प्रतिशत हो गया है। जो लड़कियां बीच में ही स्कूल छोड़ देती थीं, उन्हें कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर से जोड़ा गया है। बालिकाओं के सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए कार्य किया जा रहा है। अब उन्हें अपने गांव से बाहर भी रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। अच्छे परिणामों को देखकर राजस्थान राज्य सरकार ने यूएनएफपीए के साथ मिलकर इन योजनाओं में तेजी लाने का निर्णय किया है।

मध्य प्रदेश

लाइफ स्किल्स का विकास

मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा संचालित लाइफ स्किल्स एजुकेशन पहल के माध्यम से बच्चों में जीवन कौशल विकसित किया जा रहा है। यूएनएफपीए के सहयोग से राज्य के कम उम्र के नागरिकों को लैंगिक असमानता, बाल विवाह जैसी कुरीतियों से लड़ने की प्रेरणा दी जा रही है। इसके अलावा उन्हें स्वास्थ्य एवं करियर के लिए जागरूक किया जा रहा है।

शैलजा त्रिपाठी

स्रोत: नन्ना हेटमैन/मेगनम फोटो

मध्य प्रदेश के मंडला जिले में रहने वाले छात्र समीर मरकाम को तम्बाकू सेवन की लत लग गई थी। उमंग क्लासरूम सेशन के दौरान समीर ने जब तंबाकू सेवन के दुष्परिणामों को जाना तो नशा मुक्त होने का निर्णय लिया। समीर का कहना है "मैं तंबाकू सेवन की लत से ग्रसित था। मैं इस आदत को छोड़ना चाहता था। उमंग क्लासरूम सेशन के दौरान, मुझे जो लाइफ स्किल्स हासिल हुईं, उन्होंने मेरे लिए व्यसन मुक्ति का रास्ता खोला। आज मैं राहत महसूस करता हूं।"

खरगोन जिले के भिकान गांव निवासी आईटीआई छात्र ऐश्वर्य मलाकर का कहना है "लाइफ स्किल्स एजुकेशन पहल यानी जीवन तरंग के कारण मेरे जीवन में कई बदलाव आए हैं। मैं अब दूसरों की इज्जत करता हूं, अपनी बात को स्पष्ट ढंग से पेश करता हूं। मेरे आत्म विश्वास में वृद्धि हुई है और अब मैं अपनी समस्याओं को साझा करने में झिझकता नहीं हूं।"

उमंग स्कूल हेल्थ एवं वेलनेस प्रोग्राम राज्य सरकार द्वारा संचालित लाइफ स्किल्स एजुकेशन पहल का हिस्सा है। इसे यूएनएफपीए और भारतीय ग्रामीण महिला संघ के सहयोग से चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि युवा पीढ़ी को उनके स्वास्थ्य एवं भविष्य के प्रति जागरूक किया जाए, जिससे वह एकजुट होकर बाल विवाह और लैंगिक असमानता जैसी कुरीतियों से लड़ सकें।

उमंग स्कूल हेल्थ एवं वेलनेस प्रोग्राम मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा कक्षा 9 से कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए संचालित किया जा रहा है और इसमें यूएनएफपीए का पूरा सहयोग मिल रहा है। इसे अभी तक मध्य प्रदेश के 52 जिलों में स्थित 9306 सरकारी स्कूलों में लागू किया गया है,जिससे 24 लाख छात्र एवं छात्राओं को लाभ हुआ है। इसी मुहिम के तहत 12,599 शिक्षकों की ट्रेनिंग भी हुई है।

जीवन तरंग मुहिम के माध्यम से मध्य प्रदेश में आईटीआई में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को रोजगार पाने के काबिल बनाया जा रहा है।

इस मुहिम का उद्देश्य प्रदेश की 238 आईटीआई संस्थान में पढ़ने वाले 59000 का भविष्य निर्माण करना है। अभी तक 46 आईटीआई में कार्यरत 176 ट्रेनिंग अधिकारियों को इस मुहिम के तहत ट्रेनिंग दी जा चुकी है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, जहां हर 5 में से 1 व्यक्ति 10 से 19 वर्ष की आयु सीमा का है।

किशोरावस्था ऐसी स्थिति है जब मनुष्य में शारीरिक और मानसिक बदलाव आते हैं। यह बदलाव स्त्रियों में अधिक जटिल होते हैं क्योंकि उन्हें लैंगिक असमानता और बाल विवाह जैसी कुरीतियों का सामना करना पड़ता है।

यह मुहिम कई तरह से महत्वपूर्ण है। एनएफएचएस -5 (2019-2021) के अनुसार 15 से 17 आयु वर्ग की 5187 लड़कियां गर्भधारण कर चुकी थीं या प्रसव के बाद अपनी पहली संतान को जन्म दे चुकी थीं। सर्वे के अनुसार जिन औरतों ने कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की थी (8प्रतिशत)या 5 साल से कम स्कूली शिक्षा ग्रहण की थी (19प्रतिशत), वह कम उम्र में गर्भवती हो रही थीं। वहीं सर्वे के अनुसार जिन औरतों ने 12 साल से अधिक समय तक शिक्षा ग्रहण की थी, उनमें से सिर्फ 2 प्रतिशत महिलाएं ही कम उम्र में गर्भधारण कर रही थीं। इस सर्वे से यह साबित हुआ कि शिक्षा और कम उम्र में गर्भधारण का सीधा संबंध है। कम उम्र में मातृत्व सुख प्राप्त करने वाली लड़कियों के कई प्रश्न होते हैं। इन प्रश्नों का जवाब देने वाले परामर्शदाता महंगी फीस लेते हैं। इस परेशानी को दूर करने के लिए यूएनएफपीए और मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षा विभाग ने एक साथ मिलकर उमंग हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। इस टोल फ्री सेवा के माध्यम से सभी शिक्षित एवं अशिक्षित माताओं को अपने प्रश्नों के जवाब प्राप्त हो सकेंगे। मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग के लिए ट्रेनिंग प्राप्त काउंसलर नियुक्त किए गए हैं। अभी तक 2 लाख अभिभावकों ने उमंग हेल्पलाइन सेवा का इस्तेमाल किया है। उमंग प्रोग्राम को मुख्यमंत्री पुरस्कार भी प्रदान किया गया है।

शमसुनिसा खान, जो शासकीय गठामंदिर विद्यालय में टीचर हैं, के अनुसार लाइफ स्किल्स एजुकेशन पहल के कारण विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच की दूरी कम हुई है। पहले छात्राएं अपनी बात कहने में संकोच करती थीं। यदि उनका शोषण होता था तो, वह खामोश रहती थीं।अब स्थिति बदल गई है। किसी भी अप्रिय स्थिति की जानकारी छात्राएं तुरंत विद्यालय प्रशासन को देती हैं। लाइफ स्किल्स एजुकेशन पहल से एक भरोसा स्थापित हुआ है।

यूएनएफपीए टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के मुद्दे पर भी काम कर रही है। इसी से लिंग आधारित हिंसा को बढ़ावा मिलता है। लड़के- लड़कियों को शिक्षित करने के लिए यूएनएफपीए ने ट्रेनिंग बुकलेट उज्ज्वल का सृजन किया है। राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में 185 प्रतिभागियों को ट्रेनिंग दी गई है। नोडल शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए 9000 सरकारी स्कूलों उपलब्ध कराए गए। गाइड बुक में कक्षा 9 से कक्षा 12 के विद्यार्थियों पर ध्यान दिया गया है।

खरगोन जिले के भिकान गांव निवासी नरेन्द्र सिंह चौहान, जो कि आईटीआई छात्र हैं कहते हैं "लाइफ स्किल्स एजुकेशन ने न केवल हमारे व्यक्तित्व निर्माण का काम किया है बल्कि जीवन के प्रति हमारे नजरिए को भी बदला है। जीवन तरंग कार्यक्रम में हमने दूसरों की भावनाओं को समझना और उसकी इज्जत करना सीखा है।"

इन कार्यक्रमों से दिव्या और उनकी बहन की तरह पब्लिक चैंपियन निकल रहे हैं। दिव्या राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षक हैं। दिव्या छतरपुर जिले के टिकुरी गांव में किशोरावस्था में प्रवेश करने वाली लड़कियों को शिक्षित करने का कार्य करती हैं। वह लड़कियों के साथ पोषण, प्रजनन स्वास्थ्य, लैंगिक मुद्दों पर बात करती हैं और सभी जिज्ञासाओं को शांत करती हैं। दिव्या कहती हैं "मंब स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हूं। मुझे परिवार नियोजन, सेक्सुअल एवं प्रजनन स्वास्थ्य की बारीकी से जानकारी है क्योंकि मेरी मां आशा वर्कर है। यह ऐसे मुद्दे नहीं हैं, जिन पर बात करते हुए झिझक पैदा हो। यह मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए गम्भीर मुद्दे हैं और इन पर बात होनी बेहद जरूरी है।"

यूएनएफपीए राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में भी गहरी रुचि ले रही है। पोषण, सेक्सुअल एवं प्रजनन स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, हिंसा एवं चोट से बचाव, नशा उन्मूलन और गैर संचारी रोग, वह छह विषय हैं, जिन पर राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का विशेष ध्यान है। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को इस काबिल बनाना है कि वह अपने स्वास्थ्य से जुड़े निर्णय

लाइफ स्किल्स एजुकेशन

9,292
स्कूलों में लाइफ स्किल्स एजुकेशन योजना लागू की गई।

कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के
24 लाख
विद्यार्थियों को इस योजना के तहत लाभ हुआ।

12,599
शिक्षकों की लाइफ स्किल्स एजुकेशन योजना के तहत ट्रेनिंग हुई।

जीवन तरंग मैनुअल के तहत भोपाल, इंदौर, उज्जैन जोन के
500
अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

स्रोत: यूएनएफपीए

स्रोत: यूएनएफपीए

डिजिटल सखी

दुर्गा, प्राची, आकांक्षा जैसी युवतियां डिजिटल सखी के रूप में जानी जाती हैं। यह स्मार्ट फोन के माध्यम से समाज की सकारात्मक कहानियों को सामाजिक बदलाव के लिए प्रसारित करने का कार्य करती हैं।

"मुझे इस कार्यशाला से पहले वीडियो बनाना नहीं आता था। अब मुझे वीडियो बनाने के साथ साथ स्मार्ट फोन से कहानियां कहना भी आ गया है।

दुर्गा, इंदौर

पहले कैमरे के आगे, मेरा आत्म विश्वास डगमगा जाता था। अब नियमित अभ्यास के कारण मैं विश्वास से कहानियां सुनाती हूं।

प्राची मोरी, भोपाल

स्टोरीटेलिंग सत्र ने युवाओं को जोड़ने का काम किया है। अब हम युवाओं को वीडियो भेजकर विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर जानकारी देने का कार्य कर रहे हैं।

आकांक्षा, भोपाल

स्रोत: नन्ना हेटमैन/मेग्नम फोटो

सही ढंग से ले सकें। युवाओं को पोषण, सेक्सुअल एवं प्रजनन स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य की सही जानकारी देने के लिए युवा प्रशिक्षक नियुक्त किए गए हैं।

यूएनएफपीए 13 जिलों में युवाओं से तालमेल स्थापित करने में लगी हुई है। जागरूकता अभियान के साथ ही यूएनएफपीए राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम जैसी स्वास्थ्य सेवाओं से समाज को जोड़ने का काम करती है। अभी तक 102 किशोरावस्था स्वास्थ्य क्लीनिक में 102 काउंसलर नियुक्त किए गए हैं, जो युवाओं की सभी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हैं। किशोरियों के लिए यूएनएफपीए के द्वारा एक्शन फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स मुहिम चलाई जा रही है।

जेंडर आधारित हिंसा से निपटने के लिए यूएनएफपीए ने सितंबर 2022 में महिला एवं बाल विकास विभाग और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के सौजन्य से तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से यूएनएफपीए ने लैंगिक असमानता और मीडिया की भूमिका पर इस साल की शुरुआत में सेमिनार आयोजित किया था।

महिलाओं की विकास स्थिति

6 साल या उससे ज्यादा उम्र की लड़कियों की स्कूल जाने की दर 64 प्रतिशत (एनएफएचएस 4)से बढ़कर 67.5 प्रतिशत (एनएफएचएस 5) हो गई है।

15 से17 साल की लड़कियों के गर्भवती होने की दर 7.3 प्रतिशत (एनएफएचएस 4) से घटकर 5 प्रतिशत (एनएफएचएस 5) हो गई है।

घर के मामलों (3 फैसलों) में शादीशुदा महिलाओं द्वारा निर्णय लेने की/सहभागिता करने की दर 82.8 प्रतिशत (एनएफएचएस 4) से बढ़कर 86 प्रतिशत (एनएफएचएस 5) हो गई है।

राज्य ने महिला विकास संकेतकों पर सुधार किया है। 6 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियों के स्कूल जाने के मामले में इजाफा हुआ है। यह आंकड़ा 64 प्रतिशत (एनएफएचएस -4) से बढ़कर 67.5 प्रतिशत (एनएफएचएस -5) हो गया है।15 से 19 वर्ष की आयु में गर्भधारण करने वाली स्त्रियों की संख्या में भी गिरावट आई है। यह आंकड़ा 7.3 प्रतिशत (एनएफएचएस -4) से घटकर 5 प्रतिशत (एनएफएचएस -5) हो गया है। शादीशुदा महिलाओं की परिवार से जुड़े निर्णयों में सहभागिता में भी वृद्धि हुई है। यह आंकड़ा 82.8 प्रतिशत (एनएफएचएस -4) से बढ़कर 86 प्रतिशत (एनएफएचएस -5) हो गया है।

शादीशुदा महिलाओं से होने वाली घरेलू हिंसा के मामले में कमी आई है। यह आंकड़ा 33.3 प्रतिशत से घटकर 28.1 प्रतिशत पर आ गया है।

यूएनएफपीए राज्य के दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचने का कार्य कर रही है। दूरसंचार के विभिन्न माध्यमों के द्वारा उमंग हेल्पलाइन सेवा की जानकारी युवाओं तक पहुंचाई जा रही है। किशोर एवं किशोरियों की ट्रेनिंग के कार्यक्रम बड़े स्तर पर चलाए जा रहे हैं।

ओडिशा

डाटा लाभांश

यूएनएफपीए के ओडिशा स्थित कार्यालय द्वारा डाटा विश्लेषण किया जाता है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे में मौजूद कमियों को दूर किया जा सके और सिनापाली जैसे क्षेत्रों में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा मिले।

नैना गौतम

ओडिशा में बीते कुछ वर्षों में मातृ स्वास्थ्य में सुधार देखा गया है। अब अधिक गर्भवती महिलाओं को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो रही है और संस्थागत प्रसव के मामलों में भी वृद्धि हुई है। इससे प्रसव के दौरान, माताओं और नवजात शिशुओं की जान को होने वाला खतरा कम हो गया है।

इस बात को साबित करने के लिए पर्याप्त सुबूत हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार चिकित्सा सुविधाओं के बीच होने वाले प्रसव की संख्या 85 प्रतिशत (एनएफएचएस 4) से बढ़कर 92 प्रतिशत (एनएफएचएस 5) हो गई है। यह बढ़ोतरी एनएफएचएस 3 (38 प्रतिशत) की तुलना में दोगुनी से भी अधिक है। आज 82 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व देखरेख डॉक्टर द्वारा की जाती है। पहले यह जांच नर्स, एएनएम कार्यकर्ता द्वारा की जाती थी।

राज्य में प्रसूति पूर्व जांच में बढ़ोतरी देखी गई है। यह आंकड़ा 64 प्रतिशत (एनएफएचएस 4) से बढ़कर 77 प्रतिशत (एनएफएचएस 5) हो गया है। शिशु के जन्म के बाद, अस्पताल में पोस्टनेटल केयर उपलब्ध कराई जाती है। सर्वे के अनुसार 94 प्रतिशत माताओं को प्रसव के दो दिन के भीतर पब्लिक हेल्थ सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं जबकि 93 प्रतिशत माताओं को प्राइवेट हेल्थ सुविधाएं

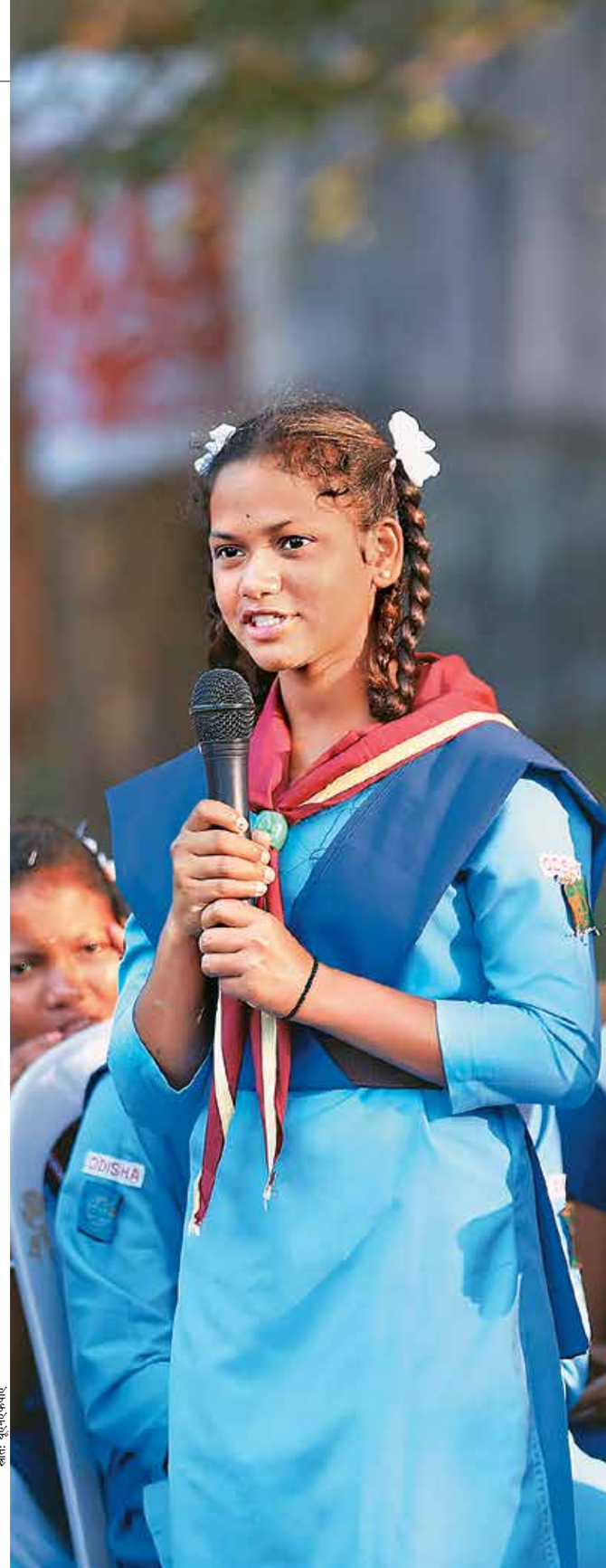

स्रोत: यूएनएफपीए

स्रोत: गैटी इमेजेज

मुख्य बिंदु

संस्थागत प्रसव के मामलों में हुई वृद्धि

85% (एनएफएचएस 4) से बढ़कर 92 (एनएफएचएस 5) प्रतिशत पहुंचा

घर में होने वाले प्रसव में आई गिरावट

15% (एनएफएचएस 4) से 8% (एनएफएचएस 5) पहुंचा

उपलब्ध कराई जा रही हैं।

हालांकि यह प्रगति पूरे राज्य में एक समान नहीं है। दक्षिणी ओडिशा में कुछ ऐसे इलाके हैं, जिनकी स्वास्थ्य सेवाएं राज्य की औसत स्वास्थ्य सेवाओं की तुलना में कमतर हैं। दक्षिणी ओडिशा के नुआपाड़ा जिले के सिनापाली ब्लॉक में घर में होने वाले प्रसव की संख्या सबसे अधिक है।

सिनापाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर अत्यधिक दबाव इसलिए भी था क्योंकि इसे 32 दूरस्थ गांवों की स्वास्थ्य सेवाओं का बंदोबस्त करना पड़ता था।

स्थिति का जायजा लेते हुए, यूएनएफपीए ने मातृ मृत्यु की चुनौती से निपटने के लिए सूक्ष्म स्तर पर डाटा विश्लेषण किया है। यूएनएफपीए के ओडिशा स्थित कार्यालय ने प्राथमिक स्तर के स्वास्थ्य केंद्रों की जब जांच की तो यह पाया कि स्थिति बेहद खराब है। ब्लॉक स्तर पर मौजूद कमियों को पहचानने और उनमें सुधार करने के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा डाटा एकत्रित किया गया। समाज की भागीदारी के कारण वह सभी जरूरी जानकारियां उपलब्ध हो सकी हैं, जिनका इस्तेमाल स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए किया जाना है। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय स्तर पर प्लान तैयार किए जा रहे हैं और उन्हें लागू किया जा रहा है।

संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए, लक्ष्य आधारित नीति बनाई जा रही है और इसका कई जगह लाभ देखने को मिल रहा है। प्रसव पूर्व एवं प्रसव के बाद, दवाओं एवं खानपान की वस्तुओं को उचित ढंग से उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। जिन गांव में स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव

मुख्य बिंदु

1. प्रसव की तिथि को ट्रैक किया जाता है।
2. जिन गर्भवती महिलाओं की स्थिति असामान्य होती है, उन पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
3. सुरक्षित एवं आरामदायक प्रसव प्रक्रिया के लिए स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा अग्रिम योजना विकसित की जा रही है।
4. दुर्गम अंचलरे मलेरिया निराकरण मुहिम के तहत विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं।
5. प्रसव पूर्व देखभाल और प्रसव के बाद देखभाल को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। गर्भवती महिलाओं के लिए जरूरी उपकरण, दवाएं और खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
6. संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए प्रति माह नए तरीके से काम किया जा रहा है।
7. संस्थागत प्रसव की तरफ आकर्षित करने के लिए बुनियादी ढांचे की तस्वीर बदली जा रही है।
8. प्रसव पूर्व देखरेख और प्रसव के बाद होने वाली देखरेख का विशेष ध्यान रखा जा रहा है।
9. प्रगति को जांचने के लिए उचित व्यवस्था की गई है।

है, वहां और अधिक प्रयास करने की जरूरत है, जिससे प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद मिलने वाली सुविधाएं में सुधार आए और मातृ मृत्यु दर कम हो। इस मुहिम की प्रगति पर नजर रखने हेतु जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।

एएनएम कार्यकर्ता ऐसी गर्भवती महिलाओं को चिन्हित करती हैं, जिनकी प्रसव प्रक्रिया जटिल मालूम होती है। ऐसी महिलाओं को रेड कार्ड दिया जाता है। इन महिलाओं का विशेष ध्यान रखा जाता है और इन्हें उच्च स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। एनीमिया से ग्रसित महिलाओं को कैंप लगातार आयरन की गोलियां वितरित की जाती हैं।

संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए गर्भवती महिलाओं की प्रसव तिथि की जानकारी पहले से प्राप्त की जाती है। आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों को गर्भवती महिलाओं की प्रसव तिथि की जानकारी दी जाती है, जिससे वह संस्थागत प्रसव पर नजर बनाए रखें और महिलाओं को उच्च स्तरीय सेवा प्रदान कर सकें।

एएनएम द्वारा संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए, गर्भधारण के सातवें महीने में हर गर्भावती महिला को स्पेशल प्लान दिया जाता है, जिससे महिला प्रसव के लिए अधिक तैयार हो जाती है। एएनएम और अन्य स्वास्थ्य कर्मी गर्भवती महिला के घर जाकर बातचीत करते हैं। जिन गर्भवती महिलाओं के घर दुर्गम इलाकों में हैं, उन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मेटरनैटी वेटिंग होम, जिसे स्थानीय भाषा में "मां गृह" कहा जाता है कि सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।

मलेरिया से निपटने के लिए "दमन" मुहिम चलाई जा रही है। "दुर्गम अंचलरे मलेरिया निराकरन" यानी दमन के माध्यम से महिलाओं और बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जिला प्रशासन के मुताबिक बीते कुछ वर्षों में किए जा रहे प्रयास से मलेरिया के मामलों में कमी आई है। डाटा को एकत्रित करने, उसका विश्लेषण करने और फिर ठोस क़दम उठाने से बुनियादी ढांचे में मौजूद कमियों में सुधार आ रहा है। हैल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अनुसार संस्थागत प्रसव की संख्या में वृद्धि हुई है। नवंबर 2022 के अंत तक संस्थागत प्रसव की संख्या 70 प्रतिशत से बढ़कर 92 प्रतिशत हो गई है। इसके अतिरिक्त मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी आई है।

यूएनएफपीए अब जमीनी स्तर पर काम करने वाले स्टाफ के साथ मीटिंग कर के प्रगति का जायजा ले रही है। इसी आधार पर भविष्य की योजनाएं बनाई जानी हैं। ऐसा विश्वास किया जा रहा है कि इन प्रयासों से सिनापाली में मातृ स्वास्थ्य बेहतर होगा और ओडिशा में मातृ मृत्यु दर में गिरावट आएगी।

स्रोत: आउटलुक

स्रोत: गैटी इमेजेज

स्रोत: यूएनएफपीए

बिहार

युवाओं की बदलती जिन्दगी

बिहार राज्य सरकार और यूएनएफपीए के साझा प्रयास से तालीम -ए - नौबलीगान पहल के माध्यम से मदरसों में पढ़ने वाले लाखों गरीब मुस्लिम विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने का काम किया जा रहा है। इन युवाओं को कौशल विकास के जरिए रोजगार के लायक बनाया जा रहा है।

नैना गौतम

सोमिया नाज, जो कि मदरसे में पढ़ने वाली छात्रा हैं, कुछ समय पहले संसाधनों की कमी के कारण अपने एथलीट बनने के शौक को पूरा नहीं कर पा रही थी। तालीम -ए - नौबलीगान पहल के कारण, सोमिया ने अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया और 100 मीटर दौड़ में कामयाबी हासिल की। इस जीत ने सोमिया को हौसला दिया और अपने सपने को पूरा करने की दिशा दिखाई।

नाज अकेली लड़की नहीं हैं, जिन्हें बिहार सरकार और यूएनएफपीए के साझा प्रयास से लाभ हुआ है।अभी तक 2500 सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसों के 2.5 लाख गरीब मुस्लिम विद्यार्थियों को तालीम -ए -नौबलीगान से लाभ मिला है।

इस पहल की कामयाबी का श्रेय उचित प्लानिंग को जाता है। तालीम -ए -नौबलीगान को एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह साल 2018 में दो जिलों में शुरू किया गया था। इस पायलट प्रोजेक्ट के सफर क्रियान्वन में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यूएनएफपीए, बिहार राजकीय मदरसा शिक्षा बोर्ड, जामिया मिल्लिया इस्लामिया नई दिल्ली, मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय का योगदान रहा है।

साल 2018 में पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत के बाद, तालीम -ए -नौबलीगान को साल 2020 में 1942 सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसों में लागू किया गया। इस पहल को साल 2022 तक बिहार के 38 में से 34 जिलों में लागू करने की योजना है।

युवाओं को प्रशिक्षित करने के साथ साथ, इस पहल का उद्देश्य बिहार में सेकुलर माहौल को स्थापित करना है, जहां सभी धर्म, मत के लोग प्रेमपूर्ण व्यवहार रखें।

तालीम -ए -नौबलीगान पहल को मजबूती से लागू करने के लिए नोडल शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों की सहायता ली गई है। सभी मदरसों में कार्यक्रम के सफल क्रियान्वन हेतु मदरसा प्रबंधन समिति की मीटिंग आयोजित की गईं।

मदरसों के शिक्षकों के लिए टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल विकसित किया गया है, जिससे वह विद्यार्थियों को और बेहतर ढंग से पढ़ा सकें और उन्हें आधुनिक ज्ञान से रूबरू करा सकें। अभी तक 3446 नोडल शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

इसके अलावा क्लास की अन्य गतिविधियों जैसे उपस्थिति दर्ज करना, विद्यार्थियों के रिकॉर्ड रखना का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। तालीम -ए -नौबलीगान के तहत स्वास्थ्य और करियर संबंधित परामर्श भी दिए जाते हैं।

मदरसा दारूल उलूम मुस्तफिया मधेपुरा पूर्णिया में कक्षा 8 में पढ़ने वाली रुखसाना खातून कहती हैं "अच्छी सेहत का मतलब न केवल खुद को बीमारियों से बचाना है बल्कि रोजाना अच्छी

बिहार में 10 से 24 साल के आयु वर्ग में शामिल मुस्लिम युवाओं की संख्या

56 लाख

बिहार की कुल मुस्लिम आबादी में

32%

युवा मुस्लिम शामिल हैं।

> “हमें पूर्ण विश्वास है कि यूएनएफपीए समर्थित तालीम -ए -नौबलीगान मिशन मदरसों की स्थिति को बदलने में सफल साबित होगा और इससे हम तरक्की, समृद्धि के अपने वायदे पर खरे उतरेंगे।”
>
> **अमीर सुभानी**
> चीफ सेक्रेटरी
> बिहार सरकार

स्रोत: यूएनएफपीए

मुख्य बिंदु

टारगेट विद्यार्थियों की संख्या
1.52 लाख

तालीम -ए -नौबलीगान के तहत आने वाले सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसे
1,942

कुल चिह्नित मदरसा रिसोर्स सेंटर
50

ट्रेनिंग हासिल करने वाले नोडल शिक्षकों की संख्या
3,446

स्रोत: यूएनएफपीए

आदतें विकसित करना भी है।”

बच्चों को जेंडर आधारित शिक्षा उपलब्ध कराना बहुत जरूरी है। जेंडर शिक्षा के माध्यम से ही बाल विवाह, घरेलू हिंसा जैसी कुरीतियों के प्रति जागरूकता पैदा की जा सकती है। इस प्रयास में जहां लड़के मदरसे में लैंगिक समानता का पाठ पढ़ रहे हैं, वहीं लड़कियां क्रिकेट, फुटबॉल जैसे खेलों का लुत्फ उठा रही हैं। इस योजना से 57 प्रतिशत मुस्लिम लड़कियों को लाभ हुआ है। तालीम -ए -नौबलीगान का उद्देश्य मदरसों की स्थिति को इंटरनेट आधारित एमआईएस का इस्तेमाल कर के मजबूत करना है।

सारा कार्यक्रम तीन स्तर पर होता है। जमीनी स्तर पर मदरसा मरकज हैं, जिनके अंदर 40 मदरसे आते हैं। इनकी स्थापना शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों की ट्रेनिंग, स्वास्थ्य एवं करियर संबंधी काउंसलिंग और किशोरावस्था में प्रवेश कर रहे बच्चों के विकास के लिए हुई थी।

अगले स्तर पर 10 आरआरसी यानी रीजनल रिसोर्स सेंटर हैं, जो शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ रखने वाले 200 मदरसों पर नजर रखते हैं।

उच्च स्तर पर स्टेट रिसोर्स सेंटर है, जो आरआरसी और एमआरसी को व्यवस्थित करता है। स्टेट रिसोर्स सेंटर का मुख्य काम नीति निर्माण और उनका अनुपालन सुनिश्चित करना है।

मोबाइल एप्लीकेशन और एमआईएस विकसित कर के प्लानिंग, रिपोर्टिंग, समीक्षा हेतु तकनीकी रूप से समृद्ध वातावरण विकसित किया गया है। तालीम -ए -नौबलीगान का व्या असर देखने को मिला है।

बिहार सरकार में चीफ सेक्रेटरी आईएएस अमीर सुभानी कहती हैं “हमें पूर्ण विश्वास है कि यूएनएफपीए समर्थित तालीम -ए -नौबलीगान मिशन मदरसों की स्थिति को बदलने में सफल साबित होगा और इससे हम तरक्की, समृद्धि के अपने वायदे पर खरे उतरेंगे।”

10 से 24 साल के आयु वर्ग में शामिल युवा मुस्लिम, बिहार में मुस्लिम जनसंख्या का 32 प्रतिशत हैं। 32 प्रतिशत यानी 56 लाख मुस्लिम युवाओं के लिए संचालित तालीम -ए -नौबलीगान चाहे अल्पसंख्यकों के हितों के लिए है मगर इससे पूरा राज्य का विकास हुआ है।

यूएनएफपीए

तीन परिवर्तनकारी लक्ष्य

- **शून्य** परिवार नियोजन की अपूर्ण आवश्यकता
- **शून्य** लिंग आधारित हिंसा और जानलेवा गतिविधियां
- **शून्य** बचाव योग्य मातृ मृत्यु

यूएनएफपीए इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकारी संस्थाओं एवं स्वयं सहायता समूहों की मदद ले रही है। इस साझेदारी से लैंगिक समानता, सेक्सुअल एवं प्रजनन स्वास्थ्य मुद्दे, युवाओं में स्किल डेवलपमेंट, नीति निर्माण के लिए जनसंख्या डाटा एकत्रित करने का कार्य हो रहा है।

UNFPA India Country Office
55, Lodi Estate, New Delhi 110003

Phone: 011-46 532333
Fax: 011-24628078

Email:
india.office@unfpa.org

Website:
https://india.unfpa.org

@UNFPAIndia
@UNFPAIndia
@UNFPAIndia
@UNFPAIndiaOfficial